बिहार सरकार
मुख्यमंत्री का कार्यालय
(जनसंपर्क कोषांग)
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-128
10/03/2026

समृद्धि यात्रा के दौरान सुपौल में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री

पटना, 10 मार्च 2026 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आज सुपौल जिला के निर्मली अनुमंडल कार्यालय मैदान में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी यहां इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर, 2005 को पहली बार बिहार में एन०डी०ए० की सरकार बनी थी, तब से राज्य में कानून का राज है और हमलोग लगातार विकास के काम में लगे हुये हैं। 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में काफी विवाद होता था, आये दिन हिन्दू–मुस्लिम के बीच झगड़े होते थे। शिक्षा व्यवस्था बदहाल था। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली की आपूर्ति बहुत कम जगह हो पाती थी। हमलोग पिछले 20 साल से निरंतर बिहार के विकास के काम में लगे हुए हैं। अब बिहार में किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। पूरे राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल कायम है। हिन्दू–मुस्लिम विवाद को खत्म करने के लिये वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गयी है। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा–झंझट नहीं होता है। चोरी आदि की घटनायें नहीं हो, इसे लेकर वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिन्दू मंदिरों की घेराबंदी की जा रही है। सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हमलोगों ने बड़ी संख्या में नये स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले लड़के–लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलायी गयी। वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2 लाख 58 हजार सरकारी शिक्षकों की बहाली की गयी है। वर्ष 2006 से 3 लाख 68 हजार नियोजित शिक्षकों की बहाली की गयी, जिसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28 हजार 976 सरकारी शिक्षक बन गये हैं। उसके बाद सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बी०पी०एस०सी० की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाय। इसके लिए उन्हें 5 मौका देना तय किया गया। अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2 लाख 66 हजार नियोजित शिक्षक पास हो गये हैं। अब केवल 73 हजार शेष बच गये हैं जिन्हें 1 मौका और दिया जायेगा। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5 लाख 24 हजार हो गयी है और 45 हजार नए शिक्षकों की बहाली बी0पी0एस0सी0 द्वारा की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39 मरीज ही आते थे यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गयी है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हर महीने औसतन 11 हजार 600 मरीज आते हैं। बिहार में पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे जिनकी संख्या अब 12

हो गयी है तथा शेष सभी 27 जिलों में नये मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जायेगा। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5 हजार 400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को ढाई हजार बेड का किया जा रहा है। साथ ही आई०जी०आई०एम०एस० को 3 हजार बेड का बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों और पुल–पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुँचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल–पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है, जिससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुँचना संभव हुआ है। वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। वर्ष 2008 से 2012 तक पहला, 2012 से 2017 तक दूसरा, 2017 से 2023 तक तीसरा कृषि रोड मैप के तहत योजना चलायी गयी जिससे अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। मछली का उत्पादन ढाई गुना से अधिक हो गया है जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप (वर्ष 2024 से 2029) के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। वर्ष 2015 में सात निश्चय के तहत (1) आर्थिक हल–युवाओं को बल, (2) आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, (3) हर घर तक बिजली, (4) हर घर नल का जल, (5) हर घर शौचालय, (6) टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा (7) अवसर बढ़े–आगे पढ़ें का काम किया गया है। वर्ष 2018 में ही हर घर बिजली पहुँचा दी गयी। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गयी। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाये जायेंगे। वर्ष 2020 से सात निश्चय–2 के तहत (1) युवा शक्ति–बिहार की प्रगति, (2) सशक्त महिला सक्षम महिला, (3) हर खेत तक सिंचाई का पानी, (4) स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव (सोलर स्ट्रीट लाईट), (5) स्वच्छ शहर–विकसित शहर, (6) सुलभ सम्पर्कता तथा (7) सबके लिये स्वास्थ्य सुविधा (टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना) सभी पर काफी काम हुआ हुआ है। सात निश्चय–2 के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जायेगा। सात निश्चय–2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकारी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया। अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है। चाहे हिन्दू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गयी है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गयी है, इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना करायी गयी जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गयी है। इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाये गये जिनमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित एवं मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। इनके रोजगार हेतु 2 लाख रुपये की दर से सहायता देना शुरू किया गया और इस सहायता को 5 वर्षों में सभी लोगों को देना था। हमलोगों ने अब तय कर दिया है कि इन सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से

जोड़कर राशि दी जायेगी। आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपये से ज्यादा राशि भी दी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की गयी। अब तक चार चुनाव हो चुके हैं। हमलोगों ने वर्ष 2013 से पुलिस में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया जिसे जीविका नाम दिया। उस समय की केंद्र सरकार ने हमलोगों के इस काम से प्रेरित होकर इसका नाम आजीविका कर दिया। अब बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या 11 लाख 5 हजार हो गयी है जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 69 लाख हो गयी है। वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू कराया गया, जिनसे अबतक 10 लाख 58 हजार जीविका दीदियां जुड़ चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 के दिसम्बर एवं 2025 के जनवरी–फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और वहां जो कमी रह गई उसको दूर करने के लिए योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा लिया जायेगा। बिहार के विकास में केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गयी। फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गयी है। वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है। बिहार में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कराया गया, जो गौरव की बात है। इन सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का नमन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आये हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास/शुभारम्भ किया गया है, इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा पहले कार्यकाल 2005–2010 तक, दूसरे कार्यकाल 2010–2015 तक, तीसरा कार्यकाल 2015–2020 तथा चौथे कार्यकाल 2020–2025 को मिलाकर हर क्षेत्र में काम हुआ है चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो। महिला सशक्तिकरण के लिए भी अनेक काम किये गये हैं। अब विकास की गति को और तेज किया जायेगा। केन्द्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए सात निश्चय–3 को लागू किया गया है। दोगुना रोजगार दोगुनी आय के अंतर्गत राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जायेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10 हजार रुपये दिये गये हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जायेगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराये जाएंगे। इसके लिए नये युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। वहीं समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार के तहत अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जायेगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जायेगी। नये बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जायेगा। कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि के तहत कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए बिहार विपणन प्रोत्साहन

निगम की स्थापना की गयी है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जायेगा। डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य के तहत राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जायेगा। एक नये एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जायेगा। सुलभ स्वास्थ्य–सुरक्षित जीवन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र बनाया जायेगा। सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लायी जायेगी। मजबूत आधार–आधुनिक विस्तार के तहत आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जायेगा जिसमें शहरों का विकास और नये नियोजित शहरों की स्थापना की जायेगी। 5 नये एक्सप्रेस–वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2–लेन चौड़ीकरण किया जायेगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाये जायेंगे। बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जायेगा। पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जायेगी। सबका सम्मान–जीवन आसान (**Ease of Living**) के तहत आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केन्द्र का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जायेगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। हमलोग विगत 2 दशक से लगातार बिहार के विकास में लगे हुये हैं। 2005 से पहले सुपौल जिला का भी बुरा हाल था। हमलोगों ने सुपौल जिले में विकास के अनेक काम कराये हैं। यहां इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गयी है। महिला आई०टी०आई० एवं सभी अनुमंडलों में आई०टी०आई० की स्थापना की गयी है। जी०एन०एम० संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गयी है। सुपौल में लोहिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। यहां कर्पूरी छात्रावास एवं बड़े पैमाने पर सड़कों एवं पुल–पुलियों का निर्माण कराया गया है। वर्ष 2008 में कोशी नदी में भीषण बाढ़ आई थी, जिससे सुपौल और सहरसा जिला काफी प्रभावित हुआ था। प्रभावित जिलों को पर्याप्त सहायता दी गई। वर्ष 2024 में प्रगति यात्रा के दौरान हम यहां आए थे। स्थानीय लोगों ने यहां की कमियों से अवगत कराया था, उन्हे दूर करने के लिए 8 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनपर तेजी से काम चल रहा है। इन कामों को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। यहां पश्चिमी तटबंध प्रमंडल निर्मली, निर्मली घेरा बाँध की मरम्मति एवं सड़क निर्माण कार्य, छातापुर एवं त्रिवेणीगंज प्रखंड में सुरसर नदी के चैनेलाइजेशन एवं क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मति का कार्य, वीरपुर अनुमंडल मुख्यालय में निबंधन कार्यालय की स्थापना, सुपौल स्टेडियम के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य, बाबा तिल्हेश्वरनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण, सिमराही बाजार में एन0एच0–27 के जंक्शन प्वाइंट पर फ्लाईओवर, त्रिवेणीगंज बाजार के बाईपास, पिपरा बाजार के बाईपास एवं सुपौल में नये बस स्टैण्ड आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों (2025 से 2030) में सुपौल जिले में अनेक काम कराये जायेंगे। रोजगार के लिए जिले की 4 लाख 12 हजार महिलाओं को 10 हजार रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जायेगी। सुपौल जिले में औद्योगिक

क्षेत्र की स्थापना कर नये उद्योग लगाये जाएंगे। डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के 235 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा 174 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केन्द्र खोला जायेगा। सभी 11 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जायेगी। सभी 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा सुपौल सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जायेगा। खेलों के लिए सुपौल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जायेगी। सबका सम्मान–जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। केन्द्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जायेगा।

जन संवाद कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी एवं ऊर्जा मंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भी संबोधित किया। जन संवाद कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नेताओं ने मुख्यमंत्री को पुष्प–गुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंटकर तथा फूलों की बड़ी माला पहनाकर उनका स्वागत किया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, विधायक श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव, विधायक श्री रामविलास कामत, विधायक श्रीमती सोनम रानी, विधायक श्री सतीश कुमार साह, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षदगण अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं आमजन उपस्थित थे।

****